CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b) During the current year, STC has contracted 1.5 lakh MT of edible oils comprising of 1,38,000 MT of RBD Palmolein and 12,000 MT of Refined Soyabean Oil, for import on Government Account to meet the requirement of the States/UTs under the PDS. Out of this, 1,05,321 MT of RBD Palmolein had already reached till 30th November, 1998 and the remaining stock is expected to arrive during December, 1998.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के रख-रखाव भंडारण आदि पर खर्च

*194. श्री बरजिन्दर सिंह:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राशन कार्ड धारी आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की ढुलाई, रख-रखाव भंडारण, खरीद व्यवस्थाओं आदि पर किया जाने वाला व्यय खरीदे गए खाद्यान्न की मूल लागत के 50 प्रतिशत से भी अधिक है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1997-98 में इस पर कुल कितना खर्च हुआ और क्या सरकार ने इस व्यय के औचित्य पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस व्यय को कम किया जा सकता है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरतनाला): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये आवंटन के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है। उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारक आम उपभोक्ताओं तक आगे वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र करते है। (ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान ढुलाई, रख-रखाव भंडारण और वसूली आदि पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया गया कुल खर्च निम्नानुसार है:-

		गेहूं		चावल	
		दर रुपये / क्विंटल	राशि करोड़ रुपये	दर रुपये / क्विंटल	राशि करोड़ रुपये
1.	अनाज की एकीकृत लागत	497.02	3976	686.75	6868
2.	वसूली और अग्रनयन प्रभार	127.86	1023	64.15	641
2.	अधिग्रहण लागत (भारित)	624.88	4999	750.90	7509
3.	वितरण लागत				
	भाड़ा	66.62	533	66.70	667
	हैंडलिंग	27.50	220	27.50	275
	भंडारण प्रभार	17.50	140	17.60	176
	ब्याज	41.50	332	49.90	499
	मार्गस्थ हानियां	5.37	43	6.20	62
	भंडारण हानियां	-0.62	-5	3.80	38

		गेहूं		चावल	
		दर रुपये/क्विंटल	राशि करोड़ रुपये	दर रुपये/क्विंटल	राशि करोड़ रुपये
	प्रशासनिक उपरिव्यय	17.75	142	17.80	178
	कुल वितरण लागत	175.62	1405	189.50	1895
4.	कुल लागत	800.50	6404	940.40	9404
	अधिग्रहण लागत की तुलना में प्रतिशत वितरण लागत	28.10		25.24	

प्रचालन के विशाल आकार और सब्सिडि की सीमा को देखते हुए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए जा रहे खर्च की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(घ) जी, हां। खर्च को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) हालांकि अनाज की वसूली मौसमी होती है फिर भी भंडारण लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम 75 प्रतिशत की औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

(ii) वसूली और संचलन अनुपात को 1:1.35 के मानदण्ड के अनुरूप रखा जा रहा है जैसाकि भाड़ा खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

(iii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग हानियों को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) रेलवे डेमरेज प्रभार के भार को कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(v) अधिशेष स्टाक को खुले बाजार में केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक मूल्य पर रिलीज किया जा रहा है।

(vi) भारतीय खाद्य निगम प्रवेश स्तर के परिणामी पदों (रिसल्टेंट एण्ट्री लेवल पोस्ट) की भर्ती पर रोक लगा कर प्रशासनिक लागत नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है और यह अपनी कर्मचारी संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 800 व्यक्तियों की कमी कर रहा है।

Criteria for Sale of onion through outlets of NAFED

*195 SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Union Government sold onion through Mobile Vans and at the outlet of NAFED at concessional rates, after hike in its price in the open market;

(b) if so, the criteria adopted for its sale through these outlets;

(c) the agencies through which NAFED procured onions and at what price; and

(d) how much profit/loss was suffered by NAFED due to sale of onion at concessional rate?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) The Union Government has initiated a scheme of public distribution of onions at a subsidised rate of Rs.10 per kg. from 14.7.98 through the static and mobile outlets of Delhi State Civil Supplies Corporation, Super Bazar, Apna Bazar, NCCF and Central Distributing Centres of NAFED. The criteria adopted for sale of onions was on first come first basis. From 1.11.98, distribution of onions was made against entries in the ration cards. The NAFED procured